

चेक भुगतान गबन मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग

चंदौली। बैंकों में लोग अपने पैसों को सुरक्षित समझते हैं अब वही बैंक वाले खून पसीने की कमाई को गटक रहे हैं। अपने पैसे के बारे में पूछने पर बैंक कर्मों धमकी भी दे रहे हैं। कुछ दिन पूर्व बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मुगलसराय में सात लाख रुपये बैंक मैनेजर और शांति कर्मचारियों द्वारा हड़प लिया गया है। पीड़ित की शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में मामला दर्ज हो गया है। विगत दिनों महेंद्र सिंह निवासी मानस नगर ने सात लाख रुपये का चेक अपने बैंक एकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किया था। जब वे कुछ दिन बाद बैंक में जाकर पता किये की हमारे चेक का पैसा खाते में आया है कि नहीं तो बैंक मैनेजर ने कहा कि आप अपना

पैसा ले लिए है आप का चेक भुज चुका है। बैंक मैनेजर की बात सुनकर महेंद्र सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। महेंद्र सिंह ने कहा कि हमने बैंक से एक पैसा नहीं लिया है तो मैनेजर ने कहा कि आप पूरा पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोहनिया से ले लिये है जब कि पीड़ित को एक पैसा किसी भी बैंक से नहीं मिला। पीड़ित ने न्याय के लिए मानवाधिकार के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह योगी से न्याय की गुहार लगाई। चेयरमैन ने पूरे मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में नई दिल्ली में भेजकर बैंक मैनेजर सहित अन्य बैंक कर्मियों के ऊपर कठोरतम कार्यवाई करने एवं पीड़ित का गबन किये गए सात लाख रुपये वापस कराने की मांग की।

एसएसबी ने दो नेपाली किशोरियों को बचाया

सिद्धार्थनगर। 43वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सीमा चौकी खुनुवा के जवानों ने मंगलवार को मानव तस्करी होने से दो नेपाली किशोरियों को बचा लिया। मानव तस्कर व किशोरियों को नेपाल पुलिस के हवाले कर दिया।

एसएसबी जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक युवक दो नेपाली किशोरियों के साथ सीमा पार कर आता दिखाई दिया। उन सभी की गतिविधियां संदिग्ध लगीं तो रोक कर पूछताछ की। अलग-अलग पूछताछ में पता चला कि नेपाल के कपिलवस्तु

जिला के तौलिहवा थाना के अलग-अलग गांव की रहने वाली दोनों किशोरियों को भारत में अच्छी जीवन शैली गुजारने के लिए साथ वाला युवक झांसा देकर ले जा रहा था। किशोरियों के साथ पकड़े गए युवक ने अपना नाम सदानंद चौधरीबहादुर निवासी भास्कर कर्मा, भीमिया गांव पालिका कपिलवस्तु (नेपाल) बताया। एसएसबी ने पकड़े गए आरोपी व दोनों किशोरियों को नेपाल पुलिस चौकी मर्यादपुर जिला कपिलवस्तु (नेपाल) के हवाले कर दिया।

जन्मतिथि की पार्टी मनाने गए युवक को होटल मालिक ने बेरहमी से पीटा बैठने को लेकर हुआ था विवाद, कर्मियों ने भी की मारपीट, दोनों ओर से केस दर्ज

जागरण संवाददाता, पटना : जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित एक होटल मालिक की दबंगई सामने आई है। बैठने के विवाद में होटल मालिक और उसके कर्मों ने एक युवक की बुरी तरह पीटाई कर दी। युवक दो दोस्तों के साथ जन्मतिथि की पार्टी मनाने होटल में गया था। युवक का आरोप है वे एक खास टेबल पर केक काटना चाहते थे।

काउंटर पर बैठे कर्मों ने इसकी इजाजत भी दे दी थी। इसी बीच होटल मालिक और कर्मों ने राड और लाठी से उनकी बुरी तरह पीटाई कर दी। युवक गोलू कुमार को काफी चोटें आई हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं, होटल मालिक का पक्ष जानने की कोशिश की गई पर उन्होंने फोन



युवक के शरीर पर जख्म के निशान।

नहीं उठाया। जक्कनपुर थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि होटल मालिक ने भी युवकों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। आरोपित होटल मालिक अंकित और कर्मों चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। गोलू कुमार

शटर बंद कर राड और लाठी से की पीटाई

पीड़ित गोलू कुमार ने बताया कि अभी हमलोग बैठे ही थे कि होटल मालिक अंकित आ गए। उन्होंने उनके साथ गाली गलौच शुरू कर दी। हमलोगों ने इसका विरोध किया तो अंकित और होटल कर्मों चंदन मारपीट करने लगे। इस बीच, प्रेम और समर होटल से निकल गए। होटल मालिक और कर्मों ने शटर बंद कर उन्हें राड और लाठी से पीटा। इससे पीट, पैर और सिर में गहरी चोटें आई हैं। प्रेम भी मामूली रूप से जख्मी हो गए। गर्दनीबाग अस्पताल में इलाज कराया।



युवक के हाथ पर निशान।

अनिसाबाद के सरिस्ताबाद पूर्वी टोला में रहते हैं। उनका बालू का कारोबार है। परसाबाद निवासी उनके साथी प्रेम कुमार की सोमवार को जन्मतिथि थी। पार्टी मनाने तीन दोस्त गोलू, प्रेम और समर सोमवार की शाम करीब चार बजे मीठापुर स्थित साइड वाक कैफे नामक होटल में

गए थे। वे एक खास टेबल पर केक काटना चाहते थे। युवकों ने बताया कि इसकी इजाजत उन्होंने होटल के काउंटर पर बैठे कर्मों से ले ली थी। उस टेबल पर पहले से कुछ ग्राहक बैठे थे। युवकों ने आग्रह कर उन ग्राहकों को भी दूसरी टेबल पर जाने को राजी कर ली थी।

Easy Guide to Make Patients Aware of Their Rights

<https://www.newsclick.in/easy-guide-make-patients-aware-their-rights>

The right to health is not justiciable in India though the Supreme Court has interpreted it to be a part of Article 21 (protection of life and personal liberty).

The apex court's judgements and the legal provisions in Drugs and Cosmetic Act, 1940, Consumer Protection Act 1986, Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002, and the Clinical Establishment Act, 2010, have helped establish the case of looking at the rights of patients as part of human rights. Drawing upon these judgements and the provisions, the National Human Rights Commission (NHRC) drafted and adopted the Charter of Patient's Rights.

With increasing cases of irrational and unethical treatment, gross overcharging by hospitals and other violations of patients' rights, the book Patients' Rights in India, written by Dr Mohamed Khader Meeran, has come in quite timely.

The book, a compendium on patients' rights, is a ready reckoner which will make them and activists aware of their legal rights. In the words of the author: "This book has been written with an intention to educate every common citizen about the legal rights they have while visiting any hospital for seeking medical care."

For instance, as per the Charter, the patient has every right to know the expected cost of his/her treatment and the hospital administration should provide written information about the charges and the expected cost of treatment, including any additional charges that may be levied. Patients also have the right to raise queries and seek clarification from the hospital administration and get defects/doubts in billing (if any) corrected/cleared. However, in most cases, hospitals don't provide such information, leading to overcharging from patients without their knowledge.

In many cases, doctors perform without informing the patient/caregiver. For example, there have several cases of insertion of intrauterine devices into women without their knowledge, let alone consent. But 'Patient's Right to Consent for Examination and Surgery', envisaged in the Charter, desists medical professionals from any such practice.

The book lays down patients' rights in an interesting format by giving references to legal cases that eventually led to specific rulings. The content is written in an easy-to-understand language and lucidly takes the reader through various technical details.

The medical field is largely hierarchical in nature with doctors and specialists being at the top rung and patients at the receiving end. Patients have little knowledge about medical technicalities and procedures involved. Therefore, the doctor-patient relationship is inherently unequal.

"The challenges many patients face in accessing healthcare, the concerns about the lack of evidence-based medical practice, the 'mixed-pathway', the diversity of providers, the

decay in many elements of public healthcare provisioning, the increasingly corporatised nature of private healthcare, all serve as important reminders about why we need concerted efforts to delineate patients' rights in India," writes Dr Anant Bhan (researcher, Global Health, Bioethics and Health Policy) in his foreword to the book.

Moreover, as the author notes in the preface to the book that the rights of patients "... are not included in medical education curriculum. Hence, doctors do not receive any formal education or training about rights of patients."

In this situation, a book on patients' rights by a doctor is noteworthy. As Dr Amar Jesani, editor, Indian Journal of Medical Ethics, writes in the introduction of the book: "A doctor authoring this book is also a testimony to the growing number of healthcare professionals aligning themselves with the people's interests and rights and committing themselves in the struggle to change the orientation of healthcare services."

In addition to discussing the rights contained in the Charter, the author also explains the format of various publicly funded health insurance schemes. These include state-level schemes in Maharashtra and Tamil Nadu as also the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. It takes the reader through a step-by-step process of what the schemes entail and how they can be accessed.

The issue of the right to health and patients' rights came to the fore strongly during the unprecedented ongoing pandemic. The author is vigilant to include a discussion on the 'Patients' Rights during COVID-19 Pandemic'. The NHRC played a constructive role by forming an expert committee that developed an advisory document. The concerned chapter includes the key points from the human rights advisory on right to health in the context of COVID-19 published by the NHRC.

The issue of adverse events following immunisation (AEFI) often made headlines. A chapter is devoted to explaining the concept and enlisting the AEFI—Surveillance and Response Operational Guidelines 2015.

Along with enlisting patients' rights, the book also enlists the duties of patients and other general instructions they should follow. These are helpful listings for patients and their caregivers which intend to help them go through the maze of medical procedures and documentation more systematically and in an informed manner.

The Charter was adopted by the government in 2018. However, violation of patients' rights is rampant with no remedy to the aggrieved patient/caregiver in most cases. Unless collective and sustained efforts are made by the medical fraternity, patient groups, activists and civil society organisations, establishing the rights of patients as human rights will be extremely difficult. The book is an enabling step in that direction.

हाथ से मैला ढोने की प्रथा का खात्मा: मुआवज़े से आगे जाने की ज़रूरत ...

<https://hindi.newsclick.in/Ending-Manual-Scavenging-Policymaking-Needs-Innovate-Beyond-Compensation>

इस साल की शुरुआत में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया था कि पिछले पांच सालों में हाथ से मैला ढोने से किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। यह बयान जवाबदेही से बचने का एक दोहरा प्रयास दिखायी देता है और इस बयान से मुद्दे को लेकर सरकार का नज़रिया भी सामने आ जाता है।

भारत सरकार के इस बयान के बावजूद हाथ से मैला ढोने की प्रथा और उसके नतीजे आज भी बदस्तूर जारी हैं। सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक बेजवाड़ा विल्सन के मुताबिक, देश भर में हाथ से मैला ढोने के चलते 2016 से 2020 के बीच कुल मिलाकर 472 और सिर्फ़ साल 2021 में 26 मौतें हुई हैं।

सफ़ाई कर्मचारियों के हित के लिए काम करने वाली वैधानिक संस्था राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी आयोग (NCSK) ने खुलासा किया था कि अकेले 2017 और 2018 के बीच मैला ढोने से 123 लोगों की जानें चली गयी थीं।

सीमित सरकारी प्रयास

20वीं शताब्दी के बाद के दिनों से ही सत्ता में आने वाली प्रत्येक पार्टियां हाथ से मैला ढोने को लेकर अपनी समझ को एक व्यापक फलक दे पाने में नाकाम रही हैं। ज़ाहिर है, इस सिलसिले में सरकारी प्रयासों की खासियत रही है- i) सुस्त और अक्षम वितरण तंत्र से ग्रस्त मुआवज़े की क़वायद; ii) तकनीकी हस्तक्षेपों पर ज़ोर, जिन्हें शायद ही कभी ज़मीन पर लागू किया जाता हो और iii) हाथ से मैला उठाने को बतौर रोज़गार पर रोक और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (अधिनियम) को सही मायने में लागू करने में नाकामी।

न्यायपालिका ने समय-समय पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि राज्य सरकारें अपने फ़र्ज़ का निर्वाह करें और पीड़ित परिजनों को समय पर पर्याप्त मुआवज़ा दें। सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, मद्रास, ओडिशा और केरल के हाई कोर्ट ने हाथ से मैला ढोने के चलते अपनी जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवज़ा दिलवाया है। खास तौर पर सितंबर 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को हाथ से मैला ढोने वालों की विधवाओं को 10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था, भले ही मृतक एक निजी कंपनी में कार्यरत था।

व्यावहारिक बाधाओं की व्यापक समझ की कमी के चलते हाथ से मैला ढोने वालों की दुर्दशा में बदलाव होने की संभावना नहीं दिखती है। सालों से नीतिगत हस्तक्षेपों का केंद्रबिंदु मुआवज़े और तकनीकी नवाचार तक सीमित रहा है, नतीजतन, हाथ से मैला उठाने की इस प्रथा को खत्म करने की प्रगति धीमी रही है। हमें ऐसे व्यापक समाधानों की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, जो जातिगत और लिंगगत ग़ैर-बराबरी, डिजिटल असमानता और उचित विमर्श से वित्त तक पहुंच प्रदान कर सके।

जातिगत और लिंगगत वास्तविकता को चिह्नित करना और उन्हें सामने लाना

रिपोर्टों में लंबे समय से बताया जाता रहा है कि हाथ से मैला ढोने में शामिल लोगों में से 99% दलित हैं और उनमें से 95% महिलायें हैं। इससे जुड़ा जो अधिनियम है, उसका मानना है कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा जाति व्यवस्था से पैदा होती है। हालांकि, जाति के विचारों को शामिल करने का एकमात्र तरीका कुछ समितियों में अनुसूचित जातियों (SC) के प्रतिनिधियों की सदस्यता को आरक्षित करना है। न तो मौजूदा अधिनियम, और न ही प्रस्तावित 2020 संशोधन विधेयक ने भारत के दलितों के साथ हुए इस ऐतिहासिक नाइंसाफी को दुरुस्त करने की कोशिश की है।

हाल फिलहाल और इस समय जिस तरह की घटनायें घट रही हैं, उनसे तो यही पता चलता है कि हालात बदलने वाले नहीं हैं। इस बात की संभावना नहीं दिखती कि मौजूदा सरकार इन जातिगत ग़ैर-बराबरियों की नीतियों में जीवंतता लाने के लिहाज़ से एक प्रासंगिक मानदंड के रूप में स्वीकार कर पाये। इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार ने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना कराने से इंकार कर दिया था और विसंगतियों के आधार पर 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने से भी इनकार कर दिया था। इस तरह के कार्यों के लिए 2020 संशोधन विधेयक तैयार करते समय दलित अधिकार समूहों से परामर्श नहीं करने के चलते सरकार की किरकिरी भी हुई थी। हाथ से मैला ढोने की किसी भी नीति को लेकर जातिगत ग़ैर-बराबरी के कारकों को प्रभावी अहमियत देना एक पूर्व-शर्त है, मगर इसे कर पाने में सभी सरकारें नाकाम रही हैं।

ये भी पढ़ें: दिल्ली नगर निगमों और सरकार की लापरवाही से रोज़ जा रही हैं सफाई कर्मियों की जान: एसकेयू

इसके अलावा, हाथ से मैला ढोने वालों में महिलाओं के उच्च प्रतिशत होने के बावजूद उनकी चिंताओं को नीतिगत चर्चाओं और आम बहसों में बहुत कम अहमियत मिल पाती है। इस पेशे

में लगी महिलाओं की दुर्दशा पर ध्यान केंद्रित करने से लैंगिक गैर-बराबरी पर केंद्रित समाधान निकलने की संभावना है।

वित्तीय या डिजिटल समावेशन पर कोई ध्यान नहीं

हालांकि, अधिनियम और इससे जुड़ी योजनायें पुनर्वास उपायों के हिस्से के रूप में छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करती हैं, लेकिन इन तक उनकी पहुंच शायद ही हो पाती है। मिसाल के तौर पर हाथ से मैला ढोने वाले कई लोगों की पात्रता होते हुए भी सीमित वित्तीय समावेशिता के चलते बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय उत्पादों तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती, और उसका फ़ायदा भी उन्हें नहीं मिल पाता है। जैसा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी मानता है कि इस बात को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हाथ से मैला ढोने वालों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो, इसके लिए बैंक को अपनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए।

समाज के हाशिये पर खड़े इन लोगों के सामाजिक-आर्थिक हितों की हिफ़ाज़त के लिए उन्हें वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर लाने की सख्त ज़रूरत है। जो लोग हाथ से मैला ढोने से बचते हैं, उन्हें इस प्रथा में फिर से वापस नहीं आना पड़े, इसके लिए वित्तीय लाभों तक उनकी आसान पहुंच को सुनिश्चित करने में अभी एक लंबा रास्ता तय करना होगा।

व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजिटल समावेशन कार्यक्रम को भी लागू करने की ज़रूरत है। ऐसे सार्थक और समकालीन सामाजिक-आर्थिक विकास, जो हाथ से मैला ढोने के बाहर की दुनिया में एक स्थायी जीवन जीने में सक्षम बनाता है, उसकी पहुंच डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक हो, इसकी ज़रूरत है। रिपोर्टों के मुताबिक, दलित और महिलाओं की संख्या देश में हाथ से मैला ढोने वालों में सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन दुर्भाग्य से डिजिटल भेदभाव की सबसे ज़्यादा शिकार ये ही लोग हैं।

ये भी पढ़ें: स्वच्छ भारत अभियान: एक ख्याली क्रांति

राज्य सरकारों ने इस बात को स्वीकार तो किया है और इससे निपटने की कोशिश भी की है। मसलन, पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की थी, जिसमें हाथ से मैला ढोने वाले 100 लोगों सहित 500 दलित युवा राष्ट्रीयकृत बैंकों के 'बैंकिंग संवाददाता' के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। 15,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने के बाद ये संवाददाता दलित समुदाय और बैंकों के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम कर सकते हैं और इस समुदाय को ऑनलाइन लेनदेन और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद कर सकते हैं। उन्हें

कंप्यूटर, प्रिंटर और फ़िंगर-प्रिंटिंग मशीन खरीदने के लिए ब्याज़ मुक्त ऋण दिये जाने का भी प्रस्ताव दिया गया था।

लेकिन इस योजना के लागू किये जाने की स्थिति को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह देखा जाना अभी बाकी है कि एक ऐसी योजना, जो दलित बहुल क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण और इस समुदाय में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित नहीं है, उसका प्रदर्शन राज्य में किस तरह का रहा है।

मगर ऐसा नहीं है कि जाति और लैंगिक असमानता, वित्त तक सीमित पहुंच और डिजिटल गैर-बराबरी ही देश में मैला ढोने वालों की दुर्दशा के एकमात्र निर्धारक हों। हालांकि, ऐसे कुछ कारक ज़रूर हैं, जो नीति निर्माण प्रक्रिया और हाथ से मैला ढोने के लिहाज़ से राष्ट्रीय विमर्श के दरारों में गायब हो चुके हैं।

इसलिए, सिविल सोसाइटी, वित्तीय क्षेत्र और मौजूदा डिजिटल परिवेश में प्रभावित होने वाले लोगों के साथ सरकार का बढ़ता विचार-विमर्श इस मुद्दे को समग्र रूप से हल किये जाने के लिहाज़ से अनिवार्य है। इसके अलावा, शैक्षणिक, कानूनी और व्यावसायिक बिरादरी का ध्यान हाथ से मैला उठाने वालों की वास्तविकताओं को प्रभावित करने के लिहाज़ से जाति और लिंगगत पहचान, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली की क्षमता पर केंद्रित करने की ज़रूरत है।

Arun Mishra's inappropriate comments on human rights

<https://www.deccanherald.com/opinion/second-edit/arun-mishras-inappropriate-comments-on-human-rights-1042218.html>

The comments made by the chairperson of the National Human Rights Commission (NHRC) Justice Arun Mishra on matters related to human rights on its 28th foundation day last week were inappropriate and went against the remit of the constitutional body. Mishra commended the government and praised Union Home Minister Amit Shah for his “untiring efforts” to foster peace in Jammu and Kashmir and the North-East. He made his remarks in the presence of Prime Minister Narendra Modi and Amit Shah. Both of them had spoken before Mishra, and he seemed to be endorsing their views. The NHRC chairperson should not be seen as speaking for the government, which is often accused of serious human rights violations. Mishra had in the past, when he was a judge of the Supreme Court, inappropriately praised Prime Minister Modi, and last week he praised Shah for “ushering in a new age in J&K and the North-East.” Jammu & Kashmir and the North-East are places from where many human rights violations and atrocities are regularly reported. Security forces figure as the accused in most of them and so the government is responsible and answerable for them. The NHRC has the responsibility to investigate the charges and take remedial action. To praise the government for its actions in these areas amounts to giving a clean chit to the government. It is not the task of the NHRC chairperson to give a certificate to the government on its actions, like the scrapping of Article 370, in J&K. There has, in fact, been a flood of charges of rights violations in Kashmir in the past two years and the NHRC should be concerned about them. Instead, the chairperson is seen supporting the government. Mishra also condemned the “new trend” of wrongly accusing India of human rights violations at the “behest of international” forces. This is also not a matter for the NHRC to talk about. It is for the government to defend itself against such charges.

The NHRC and state human rights commissions were created to investigate charges of human rights violations and to protect the rights of citizens through legal interventions and by other means. The rights commissions have a remedial, even adversarial, role vis-a-vis the government. That is why they have been given constitutional status and powers. They are part of the checks and balances in a democracy. They should not weaken themselves by speaking and acting like government departments. Mishra’s comments will lead to loss of trust in the body, and it is another sign of the weakening of democratic institutions in the country.

Changes in BSF Law to Bring One-Third Area in West Bengal Under Central Agency

<https://thewire.in/rights/changes-in-bsf-law-to-bring-one-third-area-in-west-bengal-under-central-agency>

The recent amendment in the Border Security Force (BSF) Act extending India's prime border protection force's jurisdiction to 50 km from the international borders with Pakistan and Bangladesh in the states of West Bengal, Punjab and Assam – an increase of 35 km from the existing limit of 15 km inside the border – will bring nearly one-third of West Bengal, and most parts of the geopolitically sensitive northern Bengal, under the jurisdiction of the BSF where they will be able to conduct searches and make seizures and arrests without intimidating the local police.

This will bring several major towns including Siliguri in north Bengal that is not only the state's second-most-important city after Kolkata but also considered the gateway to the northeast as well as Nepal and Bhutan, under the jurisdiction of the BSF, which functions under the ministry of home affairs headed by Amit Shah.

West Bengal with the longest share of international borders among all states – 2,216.7 km of border with Bangladesh – is likely to have the biggest impact of this change. The entire eastern boundary of the state goes along Bangladesh and the BSF's access will extend to Kurseong in the Darjeeling hills to the Sunderbans along the Bay of Bengal.

In contrast, Gujarat shares 506 km of international border with Pakistan, while Rajasthan and Punjab share 1,170 Km and 425 km of border with India's western neighbour respectively. Assam's share of the international border with Bangladesh is only 267.5 km.

A rough depiction of BSF's new jurisdiction in West Bengal. Photo: Facebook.

Of West Bengal's 23 districts, 10 share a border with Bangladesh. Of these, the large majority of the districts of Cooch Behar, Jalpaiguri, Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur, Darjeeling, Malda, Nadia and Murshidabad will come under the BSF's jurisdiction, apart from two-thirds of the state's largest district, North 24-Parganas and roughly one-third of South 24-Parganas.

Together, these districts account for 21 of the state's 42 Lok Sabha seats.

“Almost all major towns of Bengal's Bangladesh-bordering districts come within this 50 km limit, including several district headquarters,” said TMC Rajya Sabha chief whip and national spokesperson Sukhendu Shekhar Roy. “There are reasons to apprehend that this unilateral decision of the Centre has some hidden agenda, as they have not been able to offer a logical explanation as of now.”

The BSF's power, duties and jurisdictional limitations are described under Section 139(1) of the BSF Act giving the Union government the power to define BSF's jurisdictional limitation.

However, while Punjab chief minister Charanjit Singh Channi outrightly opposed the Union government's move, branding it as an attack on the principle of federalism, West Bengal's ruling party's response has been more measured. Their main point of opposition is the procedure – why the Union government did not consult the state before taking this decision.

Also read: Channi Says Punjab Won't Accept Centre's BSF Move, Hints At Special Assembly Session

"If it's in the national interest, they should have consulted the state. India is not a unitary form of government, it's a union of states. But the Union government made no attempt to take the states concerned into confidence. We will oppose it when it's placed in the Parliament for approval," said Roy.

He referred to the Supreme Court judgment in the Naga People's Movement of Human Rights Vs Union Of India case (November 27, 1997) that ruled that "the power to make a law providing for deployment of the armed forces of the Union in aid of the civil power of a State does not include within its ambit the power to enact a law which would enable the armed forces of the Union to supplant or act as a substitute for the civil power in the State" and that "the armed forces of the Union would operate in the State concerned in co-operation with the civil administration."

"In complete contrast to the apex court's judgment, here the Centre is ensuring its armed forces supplant and act as a substitute of the state police and there has come no question of cooperation with the civil administration of the state. It's a unilateral decision that would harm India's federal structure," said Roy.

Meanwhile, Union minister of state for home affairs Nisith Pramanik, who is from the Cooch Behar district of West Bengal, said that he did not see any reason why the state government should have any objection.

"The BSF's jurisdiction can be changed to strengthen internal security and border security. No exception has been made to West Bengal. The same is being done in Assam and Punjab keeping national security on focus," Pramanik said.

The new jurisdiction

Of the eight districts in northern Bengal, only the Sikkim-bordering hill district of Kalimpong and the Bhutan-bordering Alipurduars in the foothills will not come under the BSF jurisdiction. Both of them are tiny in size.

Of the rest, there are only a few tiny patches of land in the Cooch Behar district of northern Bengal that are 50 km away from the international border with Bangladesh. The district is bounded by Bangladesh to the south and parts of east and west, leaving only some areas in the northern and northeastern parts of the district that are beyond the 50 km limit.

Jalpaiguri, bounded by Bangladesh to the southwest, also has the international border lying just about 5-10 km outside the southeastern border of the district, beyond a slim strip of land belonging to neighbouring Cooch Behar. Most of the parts of Jalpaiguri, except for some areas towards its north, come within the 50 km range.

Almost no part of Uttar Dinajpur district is beyond 50 km. The widest part of the district is towards the south – from Radhikapur along the Bangladesh border to Khirabari along the Bihar border – and it's just about 50 km in a straight line.

Also read: MHA Extends BSF's Jurisdiction in Border States, Triggers Political Storm in Punjab

In Dakshin Dinajpur Baikunthapur border with Bangladesh to the north of the district and Berali border to the south is just about 60 km, bringing the entire stretch within 50 km distance from the border from one side or the other. Gokarna along the western border of the district is about 90 km from the international border at Hili to the east of the district but it is just about 50 km from the international border at Sapmari towards the south of the district. It is only a tract of the district towards its northwest that is beyond 50 km from the Bangladesh border.

No part of northern and southern Malda is beyond 50 km from the Bangladesh border. It is only the central-western part of the district, bordering Bihar, which lies beyond 50 km.

North Bengal coming mostly under the BSF's purview is also being seen as a politically significant development, as the region is turning into a ground for an intense political battle with the BJP giving a special focus on this region than rest of Bengal after its relatively better performance in the region in the assembly general elections held six months ago.

Apart from several BJP leaders raising the demand for a separate state of north Bengal, this region also received special treatment from the Union government in the June reshuffle. Four MPs from the state got a ministerial berth and two of them are from north Bengal, which is only one-fifth of the state. The party recently also chose an MP from north Bengal, Sukanta Majumdar, as the state unit president.

In Murshidabad of south Bengal, parts of the district headquarter town, Beherampore, located at the centre of the district will come under the BSF's jurisdiction. Most parts of north Murshidabad and about half of south Murshidabad come within the 50 km range.

Google Map depicts how the expansion of BSF jurisdiction affects Murshidabad, covering important towns in the district.

In Nadia, of the two of the widest parts of the district, the one from Ballavpara to the west to Hridaypur to the east is roughly 50 km in a straight line and the other one from Gede in the east to Nabadwip in the west is about 55 km. The district headquarters, Krishnanagar, is within the 50 km range from the international border.

In North 24-Parganas, India's second most populous district, several large towns like Habra, Ashoknagar and Basirhat will be coming under the BSF's new jurisdiction.

Google Map depicts how the expansion of BSF jurisdiction affects North 24 Parganas, covering important towns in the district.

Abuse of power feared

This move is going to have a significant political impact in the coming days, expect political observers, as the state is already in the middle of a rather bitter battle with the Union government, with the state's ruling party making frequent allegations against the Union government for the alleged abuse of central agencies to intimidate the state's ruling party leaders and bureaucrats.

The state government recently told the Supreme Court that the CBI was registering cases without seeking the state's permission, despite the state withdrawing its general approval to the CBI for taking up cases within the state borders.

"As of now, they were using the Enforcement Directorate and the Central Bureau of Investigation (CBI) to intimidate our leaders. Now, the BSF will join the bandwagon. Don't be surprised if you see, within a few months, our leaders at the grassroots level getting arrested by the BSF on charges such as drug, fake currency or cattle smuggling," said a TMC Lok Sabha MP who did not want to be identified.

Members of the civil society in the state have also mostly criticised the Centre's decision but from different perspectives.

Human rights activist Kiriti Roy, who heads the NGO, MASUM, which has been working in the Bangladesh-bordering areas since the late 1990s, has registered a protest by writing a letter to the national human rights commission. Roy alleged that "the BSF daily violated the constitutional provision of the country in the name of security", and he further feared that the instances of torture, false cases, arbitrary detention and illegal arrests would increase.

Roy said that in the last five years they had lodged a total of 240 cases accusing the BSF of extra-judicial torture, 60 cases of extrajudicial execution and eight cases of

forced disappearance. Of these, in 33 cases, the National Human Rights Commission (NHRC) has recommended compensation to the victims or to their next of kin.

“We have a number of cases where BSF did not inform local police after firing incidents. There are instances when they apprehend some people during smuggling and do not hand them over to the police – in one case, they brutally tortured a person to death and threw the body away into the river or another side of the border. If the BSF gets the power to search, make seizures and arrest any suspect, then surely they will violate the procedure of arrest, search, seizure, and the attachment which relates to the memo of arrest, seizure list, search memo, etc., prescribed in the Code of Criminal Procedure,” Roy wrote in the letter to the NHRC.

Also read: Why Amit Shah’s Decision to Expand Definition of ‘Border Area’ for BSF Defies Logic

Samirul Islam, president of the socio-cultural organisation Bangla Sanskriti Mancha that is active in several districts of the state, told The Wire that they would soon hit the streets to protest the Centre’s move. He alleged that the BSF frequently faced charges of extra-judicial torture perpetrated against people living in areas adjacent to the Bangladesh border, and with the new move, more people would have to face harassment.

“It can’t be said for sure how much effect the move will have in curbing smuggling, as the BSF should have stopped it staying within the existing jurisdiction in the first place. But it can be said for sure that this is an attempt to control and manipulate the 2024 Lok Sabha elections,” said Islam.

Adding further, he said, “It’s the Centre’s attempt to exert control using the backdoor as it failed to win the state election. Bengal and Punjab are the main targets of this plan, and Assam is merely a proxy to hide the real intentions.”

Udayan Bandyopadhyay, who teaches political science at Bangabasi College in Kolkata, did not see the move infringing upon the state’s jurisdiction.

“Theoretically, the state isn’t being deprived, as the BSF is not replacing the police, instead they are going to work in addition to the police force. The Centre has also the right to take such measures in the interest of national security. And if a central agency making arrests from the state without consulting the local administration is the point of debate...then the National Investigation Agency (NIA) already enjoys that power,” said Bandyopadhyay.

“However,” he added, “for all practical purposes, abuse of power which the BSF is frequently accused of will surely increase with the expansion of their jurisdiction.”

Jeta Sankrityayan, a former professor of physics at the University of North Bengal, who had also served as a member of the State Planning Board and worked extensively on the development of border areas, thought that the expanded jurisdiction would hamper the agency's efficiency.

“Let the police do their work and let the BSF focus on the border and its immediate neighbourhood. Otherwise, their efficiency in their primary task – to protect the border and stopping infiltration and smuggling – will be affected. There will also be a conflict with the police which leads to unnecessary chaos,” Sankrityayan, a resident of north Bengal, told The Wire.